दीवानी विविध।

माननीय न्यायमूर्ति ए. डी. कोशल, जे. के समक्ष

पिर्थी और अन्य, *याचिकाकर्ताओं*

बनाम

अधीक्षण नहर अधिकारी और एक और, -*उत्तरदाता* -

1970 की सिविल रिट संख्या 744।

29 मई, 1970। -

*उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (*1873 *का VII) - धारा* 30-ए, 30-बी और 30-एफएफ - धारा 30-एफएफ (3) में 'हो सकता है' शब्द - चाहे इसका अर्थ 'होगा' - *धारा 30-एफएफ (2) के तहत जारी नोटिस - ऐसी नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है - डिवीजनल नहर अधिकारी - क्या जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए बाध्य है - धारा 30-ए द्वारा परिकल्पित योजना का अनुमोदननिर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना - चाहे अधिकार क्षेत्र के बिना।*

अभिनिर्धारित किया जाता है कि आमतौर पर 'हो सकता है' शब्द एक कर्तव्य को इंगित नहीं करता है, लेकिन एक विकल्प प्रदान करने का प्रतीक है, लेकिन कभी-कभी 'हो सकता है' शब्द से विधायिका वास्तव में एक जनादेश जारी करती है और संबंधित प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से किए जाने वाले कर्तव्य का आदेश देती है। प्रत्येक विशेष मामले में यह उस संदर्भ के आधार पर एक प्रश्न होगा जिसमें शब्द का उपयोग किया जाता है कि क्या यह संबंधित प्राधिकरण पर एक कर्तव्य डालता है या एक विकल्प देता है। उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 की धारा 30-एफएफ की उपधारा (3) में 'हो सकता है' शब्द का अर्थ है 'होगा' या 'जरूरी'। अधिनियम की धारा 30-एफएफ की उपधारा (1) के तहत किसी जलमार्ग के विध्वंस, परिवर्तन, विस्तार या अवरोध से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को जलमार्ग की बहाली का निर्देश देने के लिए डिवीजनल नहर अधिकारी को आवेदन करने और उप-धारा (2) के तहत प्रभागीय नहर अधिकारी को उचित मामलों में अपेक्षित प्रकार की सूचना जारी करने का विकल्प दिया गया है। एक बार नोटिस जारी होने के बाद

धारा 30-एफएफ (2) के तहत एक व्यक्ति को जारी किया जाता है जो इसका पालन करने में विफल रहता है, डिवीजनल नहर अधिकारी को जलमार्ग को बहाल करने या ऐसा करने से इनकार करने की स्वतंत्रता नहीं है। वह जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए बाध्य है। उप-धारा (3) का पूरा उद्देश्य, जो स्पष्ट रूप से विध्वंस आदि से प्रभावित व्यक्ति के हित में अधिनियमित किया गया है, विफल हो जाएगा, यदि धारा 30एफएफ (3) में 'मई'

शब्द पर कोई अन्य व्याख्या की जाती है। (पैरा 4 और 6)

यह अभिनिर्धारित किया है कि इससे पहले कि कोई मंडल नहर अधिकारी अधिनियम की धारा 30-ए में परिकल्पित किसी योजना को अनुमोदित करने के अधिकार का प्रयोग कर सके, उसे उसमें विनिदष्ट प्रक्रिया और इसकी सामग्री, प्रकाशन और आपत्तियों को आमंत्रित करने, सुनने और विचार करने आदि के संबंध में निम्नलिखित धारा से गुजरना होगा। उस प्रक्रिया का अनुपालन करना एक शर्त है। योजना के अनुमोदन के लिए और जब तक उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक डिवीजनल नहर अधिकारी को धारा 30-ए की उपधारा (1) के खंड (ए) से आई (डी) द्वारा कवर किए गए मामलों के संबंध में निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसमें किसी भी मौजूदा जलमार्ग का परिवर्तन और पुन: संरेखण शामिल है। (पैरा 8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 *के तहत याचिका,* जिसमें प्रार्थना की गई है कि उत्प्रेषण, परमादेश *या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश* की प्रकृति में एक रिट *जारी की जाए,* जिसमें प्रतिवादी संख्या 12के आदेश को रद्द कर दिया जाए। *1,* दिनांक 9 जनवरी, *1970 और आगे प्रतिवादी संख्या 1970* को निदेश देते हुए। 1. *और संभागीय नहर अधिकारी, रोहतक को कानून के अनुसार नहर और जल निकासी अधिनियम की धारा 30- एफएफ के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने और पुराने चल रहे अव्यवस्थित जलमार्ग को बहाल करने के लिए कहा गया है।*

आनंद सरूप, अधिवक्ता आर.एस. मित्तल, वकील के साथ याचिकाकर्ताओं के लिए।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए महान्यायविद (हरियाणा) के वकील अशोक भान, पी.एस. जैन, वकील, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

निर्णय।

ए . डी. कौशल न्यायमूर्ति _भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस याचिका में रोहतक जिले के गोहाना तहसील के निधाना गांव के 40 भू-स्वामियों ने अधीक्षण नहर अधिकारी, पश्चिमी जमुना नहर, पश्चिम सर्कल, रोहतक (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा पारित 9 जनवरी, 1970 (अनुलग्नक 'सी') के एक आदेश पर हमला किया है। 1969 (अनुलग्नक 'बी') संबंधित डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा पारित किया गया जिसमें प्रतिवादी

संख्या 2 द्वारा ध्वस्त किए गए एक जलमार्ग को बहाल करने से इनकार कर दिया गया।

(1) याचिका को जन्म देने वाले तथ्यों को इस प्रकार कहा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की भूमि को एक जलमार्ग द्वारा सेवा दी गई थी, जिसका हिस्सा जिसे योजना अनुलग्नक 'ए' में एडी अक्षरों द्वारा नामित किया गया है (उस हिस्से को बाद में वाटरकोर्स एडी के रूप में संदर्भित किया जाता है)। 28 अगस्त, 1969 और 3 सितंबर, 1969 के बीच, प्रतिवादी नंबर 2 ने वाटरकोर्स एडी को ध्वस्त कर दिया और इसके बजाय उक्त योजना में एबीसीडी अक्षरों द्वारा नामित एक और (इसके बाद वाटरकोर्स एबीसीडी के रूप में संदर्भित) को खोद दिया। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वाटरकोर्स एबीसीडी वाटरकोर्स एडी की तुलना में उच्च स्तर पर स्थित था और नहर से सिंचाई का पानी प्रभावी ढंग से उस तक नहीं पहुंच सकता था, उन्होंने उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम की धारा 30-एफएफ की उप-धारा (1) के तहत 3 सितंबर, 1969 को डिवीजनल नहर अधिकारी, रोहतक डिवीजन, रोहतक को एक आवेदन दिया। 1873 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित), विघटित जलमार्ग एडी की बहाली के लिए। उनके संदर्भ में, जिलादार और संबंधित उप-विभागीय अधिकारी ने डिवीजनल नहर अधिकारी को बताया कि प्रतिवादी नंबर 2 ने एक मौजूदा वाटरकोर्स एडी को ध्वस्त कर दिया था, जिसे उन्होंने वाटरकोर्स एबीसीडी द्वारा बदल दिया था, और जो याचिकाकर्ताओं को उनकी भूमि के लिए सिंचाई के उचित साधन के रूप में सेवा नहीं कर सकता था। दोनों अधीनस्थ अधिकारियों ने सिफारिश की कि वाटरकोर्स एडी को बहाल किया जाए। डिवीजनल नहर अधिकारी ने तब प्रतिवादी नंबर 2 को धारा 30-एफएफ की उप-धारा (2) के तहत एक नोटिस दिया, जिसमें उन्हें वाटरकोर्स एडी को बहाल करने का निर्देश दिया गया क्योंकि यह पहले से मौजूद था। प्रतिवादी संख्या 2 ने नोटिस का पालन नहीं किया और दूसरी ओर, डिवीजनल नहर अधिकारी को एक आवेदन दिया जिसमें प्रार्थना की गई कि उनके खेतों की सीमा रेखा के साथ एक वैकल्पिक जलमार्ग के निर्माण की अनुमति दी जाए। इस आवेदन पर डिवीजनल कैनाल ऑफिसर ने पाया कि वाटरकोर्स एडी प्रतिवादी नंबर 2 के हितों के लिए हानिकारक था और वाटरकोर्स एबीसीडी, जो प्रतिवादी नंबर 2 के स्वामित्व वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा के साथ चलता था, "सबसे उपयुक्त था और इस जलमार्ग के शेयरधारकों की सिंचाई को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कहा जा सकता है"। इन परिस्थितियों में उन्होंने विघटित जलमार्ग को बहाल करने के लिए इसे अनावश्यक माना और तदनुसार आदेश अनुलग्नक 'बी' पारित किया, जिसे याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 30-बी की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत

प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संशोधित करने की मांग की क्योंकि यह अधिनियम की धारा 30-ए और 30-बी के प्रावधानों का सहारा लिए बिना मौजूदा जलमार्ग के परिवर्तन या पुनर्गठन के लिए एक योजना को मंजूरी देना चाहता है। हालांकि, नंबर 1 ने याचिकाकर्ताओं की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और डिवीजनल नहर अधिकारी के फैसले को केवल इस आधार पर बरकरार रखा कि डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा किए गए साइट निरीक्षण ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि "वैकल्पिक जलमार्ग को याचिकाकर्ताओं के हितों को संतोषजनक ढंग से पूरा करना चाहिए जैसा कि पुराने पानी से होता है-

बेशक। इस संबंध में पारित उनका आदेश (अनुलग्नक 'सी') है जिस पर निम्नलिखित आधारों पर अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के नाते हमला किया जाता है: -

(1) अधिनियम की धारा 30-एफएफ की उप-धारा (2) के संदर्भ में प्रतिवादी नंबर 2 को नोटिस जारी करने के बाद, डिवीजनल नहर अधिकारी कानूनी रूप से जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए बाध्य था यदि नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया था।

(2) वाटरकोर्स एबीसीडी प्रदान करने में प्रतिवादी नंबर 2 की कार्रवाई को मंजूरी देकर और उसके कारण से वाटरकोर्स एडी को बहाल करने से इनकार करके, डिवीजनल नहर अधिकारी ने वास्तव में और प्रभावी रूप से अधिनियम की धारा 30-ए द्वारा परिकल्पित एक योजना को मंजूरी दे दी, हालांकि, उस और निम्नलिखित धारा में वर्णित प्रक्रिया से गुजरे बिना। संभागीय नहर अधिकारी का आदेश था। इसलिए, अधिकार क्षेत्र के बिना और इसलिए लागू आदेश था।

(2) मुझे लगता है कि उपरोक्त दोनों आधारों में दम है। आधार (i) की सराहना करने के लिए, धारा 30-एफएफ के प्रावधानों का संदर्भ देना आवश्यक है, जो इस प्रकार है: -

धारा 30-एफएफ

(1) यदि कोई व्यक्ति किसी जलमार्ग को ध्वस्त करता है, बदलता है, बड़ा करता है या बाधित करता है या उसे कोई नुकसान पहुंचाता है, तो प्रभावित कोई भी व्यक्ति डिवीजनल नहर अधिकारी को आवेदन कर सकता है जो जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश देता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रभागीय नहर

अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, इस प्रकार ध्वस्त, परिवर्तन, विस्तार, बाधा डालने या क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्ति को लिखित में दिए गए नोटिस के माध्यम से अपनी लागत पर उस जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने की अपेक्षा कर सकता है, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

"(3) यदि ऐसा व्यक्ति उप-धारा (2) के तहत उसे दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने में डिवीजनल नहर अधिकारी की संतुष्टि में विफल रहता है, तो डिवीजनल नहर अधिकारी जलमार्ग को उसके मूल में बहाल करने का कारण बन सकता है।

चूककर्ता व्यक्ति से इस तरह की बहाली के संबंध में होने वाली लागत की स्थिति और वसूली करें।

(4) संभागीय नहर अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस तरह के आदेश के पारित होने के तीस दिनों के भीतर अधीक्षण नहर अधिकारी के पास अपील कर सकता है, जिसका इस तरह के आदेश पर निर्णय अंतिम होगा।

"(5) कोई भी राशि जो डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर अवैतनिक रहती है, कलेक्टर द्वारा चूककर्ता व्यक्ति से वसूल की जा सकती है जैसे कि यह भूमि राजस्व का बकाया था।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आनंद सरूप द्वारा यह तर्क दिया गया है कि धारा की उप-धारा (3) में होने वाले "हो सकता है" शब्द का अर्थ है "होगा" और यह कि धारा की उप-धारा (1) और (2) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद, डिवीजनल नहर अधिकारी जलमार्ग एडी को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए कर्तव्यबद्ध था। प्रतिवादी नंबर 2 उप-धारा (2) के तहत उसे दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसे बहाल करने में विफल रहा था। मेरी राय में, यह विवाद अपवाद नहीं है। यह सच है कि आम तौर पर "हो सकता है" शब्द एक कर्तव्य को इंगित नहीं करता है, लेकिन एक विकल्प के प्रदान करने का प्रतीक है। हालांकि, ऐसे मामले नहीं चाहते हैं जब "हो सकता है" शब्द से विधायिका वास्तव में एक जनादेश जारी करती है और संबंधित प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से किए जाने वाले कर्तव्य का आदेश देती है। प्रत्येक विशेष मामले में यह उस संदर्भ के आधार पर एक प्रश्न होगा जिसमें शब्द का उपयोग किया जाता है कि क्या यह संबंधित प्राधिकारी पर कोई

कर्तव्य डालता है या विकल्प देता है। इस संबंध में, बॉम्बे प्रांत से मार्गदर्शन उपलब्ध है । *खुशालदास एस आडवाणी,* (1) और उत्तर प्रदेश राज्य *बनाम* उत्तर प्रदेश *जोगेंद्र सिंह,* (2)। *बॉम्बे प्रांत में* वी। *खुशालदास एस. आडवाणी* (1) (सुप्रा), दास, जे., (जैसा कि वह तब थे) ने कहा:

> अधिकारियों से पता चलता है कि एक शक्ति का अर्थ लगाते समय न्यायालय 'हो सकता है' शब्द को 'आवश्यक' के रूप में पढ़ेगा, जब शक्ति का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के हित को आगे बढ़ाने के लिए होगा, जिसे हासिल करने के लिए शक्ति दी गई थी। सक्षम शब्द हमेशा संभावित होते हैं और कभी भी अपने आप में किसी भी दायित्व से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। उन्हें एक समूह के रूप में पढ़ा जाता है जहां वे कानूनी अधिकार को प्रभावित करने वाले शब्द हैं।

(1) A.LR। 1950 एस.सी. 222.

(2) ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1618.

उत्तर प्रदेश राज्य v. *जोगेंद्र सिंह (2)* (सुप्रा) *उत्तर प्रदेश अनुशासनात्मक कार्यवाही (प्रशासनिक न्यायाधिकरण) नियम, 1947 के नियम 4 के उप-नियम (2) में "मई" शब्द की व्याख्या से संबंधित है, वह उप-नियम निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: –*

> "राज्यपाल, अपने स्वयं के अनुरोध पर राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के संबंध में, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में अपने मामले को ट्रिब्यूनल को भेज सकता है।

(5) यह मानते हुए कि इस उप-नियम में "हो सकता है" शब्द का अर्थ "होगा", लॉर्डशिप ने कहा: ,

> "नियम 4 (2) राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वर्ग से संबंधित है और उन्हें राज्यपाल से अनुरोध करने का अधिकार देता है कि उनके मामलों को उप-नियम (1) के खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में ट्रिब्यूनल को भेजा जाना चाहिए। हमारे निर्णय के लिए प्रश्न यह है कि क्या नियम 4(1) में 'हो सकता है' शब्द जो राज्यपाल को विवेकाधिकार प्रदान करता है, उप-नियम (2) में 'हो सकता है' शब्द उसे विवेकाधिकार प्रदान करता है, या उप-नियम (2) में 'हो सकता है' शब्द का अर्थ वास्तव में 'होगा' या 'अवश्य' है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'हो सकता है' शब्द का अर्थ आम तौर पर 'आवश्यक' या 'होगा' नहीं होता है। लेकिन यह अच्छी तरह से तय है कि 'हो सकता है' शब्द संदर्भ के प्रकाश में 'अवश्य' या 'होगा' का अर्थ देने में सक्षम

है। यह भी स्पष्ट है कि जहां एक दायित्व के साथ एक सार्वजनिक प्राधिकरण को एक विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है, तो 'हो सकता है' शब्द जो विवेक को दर्शाता है, का अर्थ एक आदेश के रूप में लगाया जाना चाहिए। कभी-कभी, विधायिका उस प्राधिकारी की उच्च स्थिति के सम्मान में 'मे' शब्द का उपयोग करती है, जिस पर शक्ति और दायित्व प्रदान करने और थोपने का इरादा है। वर्तमान मामले में, यह संदर्भ है जो निर्णायक है। नियम 4 (2) का पूरा उद्देश्य निराश हो जाएगा यदि उक्त नियम में 'मे' शब्द को उप-नियम (1) के समान निर्माण प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के संबंध में राज्यपाल को उनके मामलों को ट्रिब्यूनल में भेजने का विवेक पहले ही दिया जा चुका था कि नियम बनाने वाला प्राधिकरण उनके संबंध में एक विशेष प्रावधान करना चाहता था जो अन्य सरकारी कर्मचारियों से अलग है। नियम 4 (1) और नियम 4 (2) के तहत, अन्यथा नियम 4 (2) पूरी तरह से निरर्थक होगा। दूसरे शब्दों में, नियम 4 (2) को लागू करने का स्पष्ट और स्पष्ट उद्देश्य राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को राज्यपाल से अनुरोध करने का विकल्प प्रदान करना है कि उनके मामलों की सुनवाई एक ट्रिब्यूनल द्वारा की जानी चाहिए, न कि अन्यथा। नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने संभवतः सोचा कि राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें ऐसा विकल्प देना वैध होगा। इसलिए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है कि नियम 4 (2) राज्यपाल पर राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने का दायित्व लगाता है कि उसके मामले को नियमों के तहत ट्रिब्यूनल को भेजा जाना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा इस तरह का अनुरोध किया गया था और इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

इन दो मामलों में की गई टिप्पणियां अधिनियम की धारा 30-एफएफ की उपधारा (3) पर पूरी तरह से लागू होती हैं। उपधारा (1) के तहत किसी जलमार्ग के विध्वंस, परिवर्तन, विस्तार या अवरोध से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को जलमार्ग की बहाली का निर्देश देने के लिए डिवीजनल नहर अधिकारी को आवेदन करने और उप-धारा (2) के तहत प्रभागीय नहर अधिकारी को उचित मामलों में अपेक्षित प्रकार की सूचना जारी करने का विकल्प दिया जाता है। अब यदि यह माना जाता है कि एक बार किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है जो इसका पालन करने में विफल रहता है, तो डिवीजनल नहर अधिकारी

या तो जलमार्ग को बहाल करने या ऐसा करने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है, उप-धारा (3) का पूरा उद्देश्य, जो स्पष्ट रूप से विध्वंस से प्रभावित व्यक्ति के हित में अधिनियमित किया गया था, आदि, पराजित हो जाएगा। जिस संदर्भ में उप-धारा में "हो सकता है" शब्द होता है, इसलिए, इसका अर्थ "होगा" या "अवश्य" माना जाना चाहिए। यह इस प्रकार है कि डिवीजनल नहर अधिकारी के पास उप-धारा (2) के तहत उन्हें जारी नोटिस के बावजूद ऐसा करने में विफल रहने के बाद प्रतिवादी नंबर 2 के विफल होने के बाद भी जलमार्ग की बहाली को अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं थी।

(6) आधार (ii) अधिनियम की धारा 30-ए और 30-बी के प्रावधानों पर आधारित है जिसे उद्धृत किया जा सकता है *extenso में* संदर्भ की सुविधा के लिए। »

धारा 30-ए

(7) (क) अधिनियम में इसके विपरीत निहित किसी बात के होते हुए भी और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अध्यधीन, संभागीय नहर अधिकारी

अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी शेयरधारक के आवेदन पर, सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करने के लिए एक प्रारूप योजना तैयार कर सकेगा, अर्थात् :-

(1) किसी भी जलमार्ग के निर्माण परिवर्तन, विस्तार और संरेखण या किसी भी मौजूदा जलमार्ग का पुन: संरेखण;

(2) एक जलमार्ग द्वारा दूसरे जलमार्ग को सेवा प्रदान किए गए क्षेत्रों का पुन: आवंटन;

(3) किसी भी जलमार्ग की परत;

(सीसी) जलमार्ग की मंजूरी से मिट्टी जमा करने के लिए भूमि का कब्जा क्या है;

(4) कोई अन्य मामला जो वाटरकोर्स से पानी की आपूर्ति के उचित रखरखाव और वितरण के लिए आवश्यक है।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई प्रत्येक योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी अनुमानित लागत, प्रस्तावित जलमार्ग का संरेखण या मौजूदा जलमार्ग का पुनर्गठन, जैसा भी मामला हो, आउटलेट का स्थल, लाभान्वित होने वाले शेयरधारकों और उससे प्रभावित होने वाले अन्य व्यक्तियों का

विवरण और योजना द्वारा कवर किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र की एक रेखाचित्र योजना निर्धारित करेगी।

धारा 30-बी

(1) प्रत्येक योजना, अपनी तैयारी के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रकाशन के इक्कीस दिनों के भीतर उसके संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित रूप और रीति में प्रकाशित की जाएगी।

(2) ऐसी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, तो डिवीजनल नहर अधिकारी योजना को या तो उसी रूप में अनुमोदित करेगा जैसा कि यह मूल रूप से तैयार किया गया था या ऐसे संशोधित रूप में जो वह उचित समझे।

"(3) अधीक्षण नहर अधिकारी, *किसी भी समय या अनुमोदित योजना से पीड़ित किसी व्यक्ति के आवेदन पर, विवरण के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर स्वत*: संज्ञान ले सकता है।

धारा 30-ए के तहत योजना, डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना को संशोधित करना;

बशर्ते कि इस तरह का संशोधन वहन किए बिना नहीं किया जाएगा। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर मिला।

(8) इससे पहले कि कोई मंडल नहर अधिकारी धारा 30-क में परिकल्पित किसी योजना को अनुमोदित करने के अधिकार का प्रयोग कर सके, उसे इसकी विषय-वस्तु, प्रकाशन और आपत्तियों को आमंत्रित करने, सुनने और विचार करने आदि के संबंध में निम्नलिखित धारा में उल्लिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा। उस प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य है। योजना के अनुमोदन के लिए और जब तक उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक डिवीजनल नहर अधिकारी के पास धारा 30-ए की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (डी) द्वारा कवर किए गए मामलों के संबंध में निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसमें किसी मौजूदा जलमार्ग का परिवर्तन और पुनर्गठन शामिल है। मेरे समक्ष यह विवादित नहीं है कि डिवीजनल नहर अधिकारी ने उस प्रक्रिया के किसी भी भाग का पालन किए बिना वाटरकोर्स एबीसीडी प्रदान करने में प्रतिवादी नंबर 2 की कार्रवाई को मंजूरी दे दी। इसलिए, उन्हें यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने वास्तव में अधिनियम की धारा 30-ए की उप-धारा (1) के खंड (ए) में परिकल्पित

एक योजना को मंजूरी दी है, जिसमें उस और निम्नलिखित धारा में निर्धारित प्रक्रिया की उपेक्षा की गई है।

(9) आधार (i) और (ii) पर मेरी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि मंडल नहर अधिकारी का आदेश 'बी' दो मामलों में अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इसे अधीक्षण नहर अधिकारी (अनुलग्नक 'सी') द्वारा पारित आदेश के साथ रद्द किया जा सकता है, जिसने इसे बरकरार रखा था।

(10) प्रतिवादी संख्या 2 के वकील ने तर्क दिया है कि डिवीजनल नहर अधिकारी और अधीक्षण नहर अधिकारी की ओर से अधिकार क्षेत्र की कमी से जुड़े मुद्दे को कभी भी दोनों में से किसी के सामने नहीं उठाया गया था और इसलिए, इसे इस याचिका की सुनवाई में नहीं लिया जा सकता है, जो उच्च न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र को लागू करता है। यह तर्क बिना किसी बल के है क्योंकि अनुलग्नक 'बी' और 'सी' के आदेश क्रमशः उन्हें पारित करने वाले अधिकारियों की ओर से अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी से ग्रस्त हैं और दोष रिकॉर्ड पर स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में यह *देवेंद्र सिंह और एक अन्य* बनाम *उप सचिव-सह-निपटान आयुक्त, ग्रामीण पुनर्वास विभाग, जुलुंदूर* मामले *में आयोजित किया गया था।* (3)

(3) 1964 पी.एल.आर. 555 (एफ.बी.) " ~

एक हीन न्यायाधिकरण के समक्ष अधिकार क्षेत्र के बिंदु पर आपत्तियां उठाने में संबंधित पक्ष की विफलता उसे रिट याचिका में उस स्कोर पर राहत प्राप्त करने से नहीं रोकेगी।

(11) परिणामस्वरूप, याचिका सफल हो जाती है, आदेश 'बी' और 'सी' को अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण रद्द कर दिया जाता है और डिवीजनल नहर अधिकारी को अधिनियम की धारा 30-एफएफ की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुपालन में वाटरकोर्स एडी को बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। अधिनियम की धारा 30-ए और 30-बी में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मौजूदा जलमार्ग के परिवर्तन या पुनर्गठन, आदि के लिए या तो स्वयं या प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन पर एक योजना तैयार करना और मंजूरी देना डिवीजनल नहर अधिकारी के लिए खुला होगा। मामले की परिस्थितियों में, मैं पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दूंगा।

।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी,

हरियाणा